किसान महापंचायत: गैरराजनीतिक होने के बावजूद राजनीति की धुरी

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

बीते करीब नौ माह से चल रहे किसान आन्दोलन का एक विराट रूप पांच सितम्बर को मुज़फ़्फ़रनगर में देखने को मिला जहां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावा अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रिकॉर्डतोड़ भीड़ उस विशाल मैदान में नहीं समा पा रही थी जहां कभी पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह रैली किया करते थे। लाखों की यह भीड़ न केवल योगी सरकार की नींद हराम करने में कामयाब हुई बल्कि मोदी को भी पैरों तले ज़मीन खिसकती नज़र आने लगी है। मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों के विरोध को लेकर पंजाब से शुरू होने वाला किसान आन्दोलन बहुत समय तक पंजाब तक सीमित न रह सका और 26 नवम्बर को उसने राष्ट्रीय रूप लेना शुरू कर दिया। पंजाब के किसान जब दिल्ली की ओर बढने लगे तो किसी को गुमान तक न था कि हरियाणा व यूपी के किसान भी बढ-चढ कर दिल्ली की ओर कूच करने लगेंगे। भाजपाई भोंपुओं ने आन्दोलन को तोड़ने व बदनाम करने की जितनी कोशिश की, आन्दोलन उतना ही प्रबल होता चला गया। इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, नकसली व मवाली तक बताया गया, लेकिन सरकार की हर चाल को विफ़ल करते हुए आन्दोलन मज़बूती से आगे बढता रहा। दुनिया के इतिहास में आज तक का यह सब से लम्बा आन्दोलन माना जा रहा है।

मात्र तीन कृषि कानूनों के विरोध को लेकर चले इस आन्दोलन ने गैरराजनीतिक होते हुए भी देश की राजनीति व सामाजिक ताने बाने पर जबरदस्त प्रभाव डाला है, वह अद्वितीय है। सबसे पहले तो इस आन्दोलन ने भाजपा की उस साम्प्रदायिक राजनीति की रीढ तोड़ डाली जिसके बल पर इसने 2013 में हिन्दू-मुस्लिम दंगे करा कर 2014 का संसदीय व 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता था। पीढी दर पीढी साथ रहने वाले हिन्दू-मुस्लिम को जिस शातिराना ढंग से भाजपा ने लड़ाया था, इस आन्दोलन ने इस लड़ाई को समाप्त करके सामाजिक भाईचारा फ़िर से बहाल करा दिया।

दुसरा बड़ा काम यह हुआ कि किसान जन साधारण यानी उपभोक्ता को यह समझाने में भी बहुत हद तक कामयाब रहा कि उक्त तीन कृषि कानून न केवल किसानों को तबाह करने वाले हैं बल्कि आम उपभोक्ता भी इसके भयंकर शिकार होने वाले हैं। आन्दोलन यह समझाने में कामयाब रहा कि उक्त कानूनों के चलते चंद देशी-विदेशी पूंजीपतियों का, तमाम कृषि उपजों की खरीद व बिक्री पर एकाधिकार होगा। यानी किसान से खरीदने का भाव भी वही तय करेंगे और उपभोक्ता को बेचने का भाव भी उनकी मुट्ठी में रहेगा। उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि किस अडाणी ने हिमाचल प्रदेश के सारे सेब व्यापार पर कब्ज़ा करके सेब उत्पादकों को रूला दिया है।

तीसरा और सबसे अहम मुद्दा किसानों ने आम जनता के सामने पूंजीवाद का वह घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया जिसे वह तरह-तरह के मेक-अप लगा कर छिपाये रहता था। आम आदमी की समझ में यह बखूबी बैठ गया कि किसान से 15 रुपये प्रति किलो के भाव से गेहूं खरीद कर के आटे को ये निर्मम पूंजीपति शानदार पैकेज करके 50 रुपये किलो बेचेगा। कोई विकल्प न होने की स्थिति में उन्हें यह आटा खरीदना ही पड़ेगा या भूखों मरना पड़ेगा। बाकी सब वस्तुऐं तो मुनाफ़ाखोरी का साधन बनी ही हुई थी अब तमाम खाद्य पदार्थ भी इसी दायरे में आ जायेंगे। उनके इस दायरे को मज़बूत करने के लिये मोदी सरकार ने भंडारण की सीमायें तय करने वाले कानून को भी रद्द करते हुए किसी भी सीमा तक भंडारण की खुली छूट दे दी।

किसान आन्दोलन को गैरराजनीतिक इस लिये कहा जाता है कि यह न तो अपने आप में कोई राजनीतिक दल है और न ही किसी दल विशेष से बंधा है। यह आन्दोलन 500 से अधिक छोटे-मोटे संगठनों से मिल कर एक संयुक्त किसान मोर्चा बना है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि यह देश को बर्बाद करने पर उतारू भाजपा की राजनीति का विरोध न करे। बस इसी विरोध करने को लेकर सरकारी भोंपू इसे अब राजनीतिक की संज्ञा देने लगे हैं। दिन ब दिन सरकारी टैक्सों का भार जनता पर बढाया जा रहा है, हर चीज़ की महंगाई दिन ब दिन बढती जा रही है। देश की तमाम सम्पत्तियां बेची जा रही हैं, लोगों से उनकी नौकरियां व रोजगार छीने जा रहे हैं। इसके विरोध में जब कोई बोलता है तो सरकार पूरी बेशर्मी से कहती है कि लोगों ने उन्हें पांच साल के लिये चुन कर यही सब करने का अधिकार दिया है। जाहिर है, ऐसे में आज जब तमाम विपक्षी दल अपनी विश्वसनीयता खोकर नाकारा हो चूके हैं तो किसान आन्दोलन ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस सरकार पर वोट की चोट करने का फ़ैसला गलत नहीं लिया है। इसी गैर राजनीतिक रणनीति के तहत चलते हुए किसानों का फ़िलहाल यही फैसला है कि भाजपा को वोट की चोट मारनी जरूरी है, बाकी जिसको चाहो वोट डालो। इसी रणनीति के ऊपर एक राजनीतिक धुरी आज बन चुकी है। तमाम गैर भाजपा दल गठबंधन बना कर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की योजनायें तेज़ी से बना रहे हैं।

मोदी की सीबीआई व इडी के डर के मारे जो नेता बिलों में घुसे हुए थे अब बाहर झांकने लगे हैं। हो सकता है कि इस ठेल-पेल में इन्हें भी आगामी सत्ता में कोई भागीदारी मिल जाये, परन्तु इतना तो तय है कि ये दल भी न तो किसानों का और न ही आम जनता का कोई भला करने वाले हैं। इनमें से किसी में इतना दम नज़र नहीं आता जो यह घोषणा कर सकें कि मोदी ने जो काले कारनामे किये हैं उन्हें पुन: अपनी स्थिति में लौटा लायेंगे, मोदी द्वारा बेचे गये राष्ट्रीय उपक्रम वापस पूंजीपतियों से छीन लायेंगे, बैंकों से लूटा गया पैसा लुटेरों से वसूल कर लेंगे, जो रोजगार खत्म कर दिये गये हैं उन्हें पुन: बहाल कर दिया जायेगा; पैट्रोलियम पर मोदी काल में बढाये गये शुल्क वापस लिये जायेंगे।

खोरी उजाड़ने के पीछे मकसद....

पेज एक का शेष

जनता के सांस लेने तक के अधिकार छीने जा सकते हैं तो वहां बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी।

सुधी पाठकों ने बीते डेढ़-दो महीनो में देखा होगा कि गरीबों की बस्ती उजाड़ते वक्त प्रशासनिक गशीनरी के हाथ-पांव कितनी फ़ुर्ती के साथ चलते हैं और फार्म हाउसों, बैंक्वेट हॉल आदि की ओर जाते वक्त इनके हाथ पांव फुलने लगते हैं; बड़ी एवं आलीशान इमारतों की ओर तो झांकने तक कि हिम्मत ये लोग नहीं जुटा पाते। वहां के लिये काग़ज-पत्तर देखने-दिखाने की बात करते हैं। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि शासक वर्ग, जिसमें न्यायपालिका भी शामिल हैं, केवल मखमल में लगे टाट के पैबंद हटाने में जुटा है।

मौत के मुंह से बाल-बाल बचा क्या पुलिस कार्रवाई करेगी ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 1 सितम्बर को दिन के 11.00 बजे कमल नामक एक व्यक्ति अपने मोटर साइकिल से संजय कालोनी से सैक्टर-22 स्थित अपने घर जा रहा था कि रास्ते में सीमेन्टड सड़क के बीच स्थित जोड़ इतना गहरा एवं पानी से भरा था कि कमल उसको समझ ही नहीं पाया और उस गैप की वजह से धड़ाम से सड़क पर जा गिरा। पीछे आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने एकदम खड़े ब्रेक मारे जो लग भी गये और बिल्कुल कमल को छूती हुई गाड़ी वही रूक गई। कैंटर ड्राईवर ने गाड़ी से उतरकर बेहाल कमल को उठाया और खुदा का शुक्र किया कि सही वक्त पर सही ब्रेक लग गये। वरना तो काम हो गया था।

जैसे-तैसे कमल की जान तो बच गयी लेकिन उसे गुम चोटें इतनी जबरदस्त लगी कि एक सप्ताह तक वह चारपाई से न उठ सका। डाक्टरों के चक्कर काटकर कई एक्सरे भी कराने पड़े, पर शुक्र है कि कोई हड्डी नहीं टूटी थी। बाल-बाल बचे कमल की आंखों में आज भी व खौफ देखा जा सकता है। क्या इस हादसे के लिए व नगर निगम जिम्मेदार नहीं है जिसने इस सड़क का ऐसा निर्माण किया है। इस जगह पर होने वाला यह न तो पहला हादसा है और न ही आखिरी है। क्या पुलिस हादसे में मर जाने के बाद ही नगर निगम के विरूद्ध कार्रवाई करेगी ?

पद्मश्री ब्रह्मदत्त को पत्नी शोक

देश के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता पद्मश्री ब्रह्मदत्त की पत्नी श्रीमती लीलावती का 8 सितम्बर को स्थानीय मेट्रो अस्पताल में देहांत हो गया व पिछले कुछ समय से बीमार थी। उनका जन्म सन् 1933 में जिला मथुरा के गांव फरहा में हुआ था। स्व. लीलावती की पुण्य स्मति में शोक सभा का आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार 19 सितम्बर, 2021 को होगा।

स्थान : सीनियर सिटीजन क्लब, सैक्टर-21ए, एशियन अस्पताल के पीछे, फरीदाबाद।

समय : प्रसाद भोज - दोपहर 1.00 बजे
शोक सभा - दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे

कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकोल का ध्यान रखें।

12 साल पुराने रेन हार्वेस्टरों की याद आई, इन से पुन: लूट कमाई का जुगाड़ बनेगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब 12 वर्ष पूर्व, करोड़ों रुपये खर्च करके नगर निगम ने 165 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाये थे। इनमें से शायद ही किसी सिस्टम के द्वारा कोई बूंद पानी की धरती में उतारी हो, वरना सभी बिल पास करा कर पैसा डकारे जाने का साधन बने। बीते सप्ताह निगम अधिकारी नींद से जागे तो उन्हें पता चला कि ये तमाम तो बेकार पड़े हैं, जिसके चलते भूजल का स्तर बढना तो दूर घटता ही चला जा रहा है। करदाता के पैसे की भयंकर बर्बादी बल्कि लूट तथा भूजल स्तर की हानि के लिये दोषी लुटेरों को पकड़ने व सज़ा देने के बजाय नई योजना यह बनाई गयी है कि फ़िर से किसी प्राइवेट कम्पनी को इन्हें संवारने व चलाने का ठेका दिया जाय तथा भूजल की, दिन-प्रति दिन मॉनिटिंग करने के लिये विद्युतीय यंत्र लगाये जायें। यानी उसी काम पर दिन-प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिये विद्युतीय यंत्र लगाये जायें। यानी उसी काम पर करदाता का माल हड़पने का दूसरा मौका।

समझने वाली बात यह है कि उक्त तमाम रेन हार्वेस्टर भी प्राईवेट कम्पनियों द्वारा ही लगाये गये थे न कि निगम के इन्जीनियरों आदि के द्वारा दर असल निगम के इन्जीनियरों का इन्जीनियरिंग से कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं और न ही उन्होंने कभी यह सीखी व पढी है। इन्हें तो केवल टेंडर निकालना, बिल पास करना व मोटे से मोटा कमीशन डकारना। हां, यदि गल्ती से कभी कोई सही पढ़ा लिखा ईमानदारी से इन्जीनियरिंग करने वाला यहां आ जाय तो उसका यहां जीना दूभर हो जाय, क्योंकि ऊपर से नीचे, अफ़सर से नेता तक सभी तो चोर इकट्ठे हो कर जाल बिछाये बैठे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टर एक बहुत ही सरल व्यवस्था है जो बरसाती पानी को ज़मीन में उतार कर भूजल स्तर को बनाये रख सकता है। पहले यह काम तालाबों आदि के माध्यम से स्वत: हो जाता था। लेकिन अब शासक वर्ग की धूर्तता एवं लालच के चलते केवल और केवल लूट-कमाई ही एक लक्ष्य रह गया है। जनहित, भूजल स्तर पर्यावरण आदि जाये भाड़ में। वरना क्या वजह हो सकती है कि करोड़ों की लागत से तैयार 165 में से एक रेन हार्वेस्टर भी काम न करे। संदर्भवश, पाठक जान लें कि निगम द्वारा लगाये एक हार्वेस्टर की लागत 10 लाख से कम नहीं आती। ऐसे ही पांच सिस्टम टाउन पार्क में भी लगे हैं जिनमें से एक बूंद पानी नीचे नहीं उतरा। इनमें से एक तो पानी में चार दिन तक डूबा रहा लेकिन क्या मजाल जो एक बूंद पानी नीचे उतर जाये क्योंकि सफ़ाई के अभावों में पत्तों व टहनियों आदि ने पानी का रास्ता रोक रखा था। सेक्टर 15 की मार्केट में केवल बिल पास कराने की नीयत से बना हार्वेस्टर इतना बेढंगा है कि पानी की बूंद वहां तक नहीं पहुंच सके। ऐसे ही सेक्टर 14 पुलिस चौकी के सामने पार्क में दो हार्वेस्टर ऐसे बने खड़े हैं जिन तक पानी पहुंच ही नहीं सकता।

कुछ समय पूर्व निगम आयुक्त मोहम्द शाइन ने 'सेव अरावली' ग्रुप से बातचीत करके इन तमाम हार्वेस्टरों की जांच एवं मुरम्मत कराने का प्रयास किया था। इस ग्रुप ने सेक्टर 16 के जेड पार्क में लगे दो में से एक की जांच करके उसकी तमाम खामियों का उल्लेख करते हुए उसे तथा ऐसे ही अन्य सभी को चालू करने के लिये एक लाख प्रति यूनिट के हिसाब से मांगे थे; परन्तु निमायुक्त चाहते थे कि वे लोग मुफ़्त में ही यह काम करा दें। यानी लूट-कमाई करें अधिकारी और काम कर के दें स्वयंसेवी!

करीब ढाई-तीन साल बाद अब फ़िर प्रशासन की नज़र इन ठप पड़े हार्वेस्टरों की ओर गयी है। वह भी इस लिये नहीं कि भूजल स्तर बढाना है, बल्कि इसलिये कि इसके नाम पर एक नई शोशेबाज़ी करके दो-चार करोड़ ठिकाने लगाये जा सकें। भूजल स्तर की मॉलिटरिंग के नाम पर जिस जीपोमीटर की बात प्रशासन कर रहा है, उसकी बजार कीमत करीब 22 हजार है लेकिन निगम को तो यह कई गुणा महंगे दामों पर ही मिल पायेगा। प्रत्येक हार्वेस्टर पर लगाने के हिसाब से 165 जीपो मीटर चाहिये; ये कितने दिन काम कर पायेंगे अथवा टिके रह पायेंगे, चोरी नहीं कराये जायेंगे, वह बात अलग से है। इसके अलावा ये मीटर बेचारे वाटर चार्ज तो नहीं करेंगे केवल पानी का स्तर बतायेंगे जो आज भी बिना इनके पता चल ही रहा है यानी मकसद भूजल स्तर उठाने का नहीं, लूट-कमाई का है।

खट्टर के 1000 हार्वेस्टर कहां गये ?

करीब तीन वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने गिरते भूजल स्तर पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए निगम क्षेत्र में 1000 रेन वाटर हार्वेस्टर लगाने की घोषणा की थी, उनमें से कहीं कोई एक भी लगा किसी शहरी को नज़र नहीं आया। हां, इन्हीं दिनों इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए एक अच्छे शहरी एवं समाजसेवी के नाते पूर्व पार्षद योगेश ढींगड़ा ने जरूर एक हार्वेस्टर लगाने का प्रयास किया था। नगर निगम से बाकायदा लिखित परमीशन लेकर उन्होंने मैट्रो रोड स्थित रोज़ गार्डन में अपने पल्ले से रेन हार्वेस्टर लगाने का काम शुरू किया था। बोरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका था कि स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा को इसका पता चल गया और उन्होंने काम रूकवा दिया।

उन्हें दिक्कत इस बात से थी कि इस काम से योगेश ढींगड़ा की ख्याति इस क्षेत्र में बढ जायेगी जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिये हानिकारक हो सकती है। यानी न खुद कुछ करना और न दूसरे को करने देना।